www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-7* *July 2025***

स्वतंत्र भारत में बिहार की पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना के विकास का अध्ययन

महेश कुमार पिन्टू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बी.एन.एम.यू., मधेपुरा, बिहार

सारांश

पिछले दो दशकों में पिछड़ी जाति के राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व में उभरते राजनीतिक समाज द्वारा पिछड़ी जातियों की संबद्ध स्वायत्तता को सीमित करने वाली उच्च जाति–नियंत्रित संस्थाओं द्वारा भेदभावपूर्ण प्रक्रियाओं और प्रथाओं को गंभीर रूप से कम किया गया था। न्यायिक और लोकतांत्रिक राजनीति की पहुँच और अधिकार आंशिक रूप से पिछड़ी जातियों द्वारा प्रतिस्थापित उच्च जाति के मजबूत लोगों की रिट और शक्ति के साथ बदल दिए गए हैं। राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर के संस्थानों, सहकारी समितियों, छोटे ठेके के काम और सरकारी गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में सवर्णों के वर्चस्व को पिछड़ी जाति की राजनीति द्वारा प्रभावी रूप से रोका गया है। प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र ने पारंपरिक सामाजिक सत्ता की वैधता को कमजोर कर दिया है, राजनीतिक उद्यमियों की एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म दिया है, और ऐसे स्थान बनाए हैं जिनमें नए समूहों को सफलतापूर्वक लामबंद किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जो राजनीतिक ताकतें उभरी हैं, उनकी जड़ें पहले से कहीं अधिक सामाजिक दरारों में हैं। हाशिए पर पड़ी जातियों द्वारा बेहतर राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ–साथ नई राजनीतिक ताकतों के उदय ने जोरदार दावा करने का विचार पेश किया है। सरकारी नौकरियों में अधिक आरक्षण, संसदीय और विधायी चुनावों में अधिक सीटों आदि के माध्यम से सरकार और प्रशासन में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए ये दावे बड़े पैमाने पर सरकार से किए जाते हैं। "सभी हित समूहों द्वारा समान अवसर की लूट" के रूप में वर्णित करता है। वास्तव में बिहार जैसे स्थानों में लोकतांत्रिक प्रथाओं का 'अनुदार' या 'असभ्य' चरित्र उसी गतिशीलता से उत्पन्न होता है जिसने लोकतंत्र के कट्टरपंथीकरण को संभव बनाया। कई लोग उत्तर–औपनिवेशिक लोकतंत्र की सीमा होने का तर्क देते हैं, प्रतिरोध और सशक्तिकरण के नए रूपों के लिए एक सक्षम कारक के रूप में सामने आता है, विशेष रूप से उत्तर–औपनिवेशिक कट्टरपंथी लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता को रेखांकित करता है। इस राजनीति की क्षमता सार्वजनिक संस्थानों तक उनकी पहुँच और राज्य की सरकार और राजनीति में प्रतिनिधित्व की सुविधा देकर पिछड़ी जातियों के लिए सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने में एक कथित सुधार के माध्यम से देखा जा सकता है।

स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता (नागरिक) महत्त्वपूर्ण अंग होती है। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिक ही संसद और विधानसभा में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्त्तव्य होता है कि वे किसी भी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी दबाव के निपक्ष होकर करे ताकि योग्य उम्मीदवार विजयी हों और सरकार अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से कर सके, परंतु व्यवहारिकता में ऐसा नहीं देखने को मिलता है।

स्वतंत्र भारत के चुनाव में आम तौर पर देखा गया है कि सभी पार्टी के नेता सर्वप्रथम अपने–अपने जातियों के कुलीन एवं प्रतिष्ठित लोगों से सम्पर्क स्थापित कर अपनी जाति और अन्य जाति के लोगों के साथ गोलबंद होकर अपने दल के नेता या पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सभी जाति के

नेता लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास करते हैं और समय–समय पर राजनीति में जातिगत राजनीतिक चेतना का भी विकास महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

इस प्रकार हम ''स्वतंत्र भारत में बिहार की पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना के विकास का अनुशीलन'' को मुख्तयतः दो कालखंडों में बाँट सकते है।

(क) स्वतंत्रोत्तर भारत से लेकर वर्ष 1989 तक का काल खंड ।

(ख) 1990 से वर्त्तमान समय तक का कालखंड ।

(क) स्वतंत्रोत्तर भारत से लेकर वर्ष 1989 तक का काल खंड ।

स्वतंत्र भारत के बिहार प्रांत में प्रथम विधानसभा का चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था जिसमें कॉंग्रेस पार्टी के नेतृत्व कर्ता डॉ0 श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। डॉ0 श्री कृष्ण सिंह भूमिहार जाति से थे। उस समय उच्च जाति के लोग बिहार की राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उस समय उच्च जाति के लोगों द्वारा ही बिहार की राजनीति का मसौदा तय किया जाता था। इसके अध्ययन के लिए वर्ष 1952 में वर्ष 1989 तक बिहार में निम्न मुख्यमंत्री बने –

क्रमांक	मुख्यमंत्री का नाम	कार्यकाल	जाति
1	डॉ0 श्री कृष्ण सिंह	29.04.1952 से 05.05.1958	भूमिहार
2	डॉ0 श्री कृष्ण सिंह	06.05.1957 से 31.01.1961	भूमिहार
3	श्री दीप नारायण सिंह (कार्यवाहक)	01.02.1961 से 18.02.1961	राजपूत
4	श्री बिनोदानन्द झा	18.02.1961 से 14.03.1962	ब्राह्मण
5	श्री बिनोदानन्द झा	15.03.1962 से 02.10.1963	ब्राह्मण
6	श्री कृष्ण बल्लभ सहाय	02.10.1963 से 05.03.1967	कायस्थ
7	श्री महामाया प्रसाद सिन्हा	05.03.1967 से 28.01.1968	कायस्थ
8	श्री सतीश प्रसाद सिंहा (कार्यवाहक)	28.01.1968 से 01.02.1968	कुशवाहा
9	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल	01.02.1968 से 22.03.1968	यादव
10	श्री भोला पासवान शास्त्री	22.03.1968 से 29.06.1968	पासवान (अनुसूचित जाति)
11	श्री सरदार हरिहर सिंह	26.02.1969 से 22.06.1969	राजपूत
12	श्री भोला पासवान शास्त्री	22.06.1969 से 04.07.1969	पासवान (अनुसूचित जाति)
13	श्री दारोगा प्रसाद राय	16.02.1970 से 22.12.1970	यादव
14	श्री कर्पूरी ठाकुर	22.12.1970 से 02.06.1971	हजाम
15	श्री भोला पासवान शास्त्री	02.06.1971 से 09.01.1972	पासवान (अनुसूचित जाति)
16	श्री केदार पाण्डेय	19.03.1972 से 29.05.1973	ब्राह्मण
17	श्री केदार पाण्डेय	28.05.1973 से 02.07.1973	ब्राह्मण
18	श्री अब्दुल गफूर	02.07.1973 से 11.04.1975	मुस्लिम
19	श्री जगन्नाथ मिश्र	11.04.1975 से 30.04.1977	ब्राह्मण
20	श्री कर्पूरी ठाकुर	22.06.1977 से 21.04.1979	हजाम
21	श्री राम सुन्दर दास	21.04.1979 से 17.02.1980	दास (अनुसूचित जाति)
22	श्री जगन्नाथ मिश्र	08.06.1980 से 14.08.1983	ब्राह्मण
23	श्री चन्द्रशेखर सिंह	14.08.1983 से 12.03.1985	राजपूत

स्त्रोत–लेखक

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि बिहार में 1952 से वर्ष 1989 तक मुख्यमंत्री का 26 कार्यकाल बना जिसमें कुल 20 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। उच्च जाति के चौदह बार, पिछड़ी जाति के पाँच बार, अनुसूचित जाति के चार बार तथा मुस्लिम जाति के एक बार मुख्यमंत्री बने। इस काल में बिहार की राजनीति में उच्च जाति के नेताओं का बोल–बाला रहा एवं उच्च जाति के लोग ही राजनीतिक भूमिकाओं में बने रहे। इस अवधि में कुछ पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के नेता भी मुख्यमंत्री बने लेकिन वे अपने जाति के लोगों को संगठित नहीं कर सके और ना ही अपने लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास कर सके साथ–ही अपने जातिगत वर्चश्व को भी स्थापित नहीं कर सके। पिछड़ी जाति के नेता अपनी छवि को पूरे बिहार स्तर पर उभारने में असफल रहें, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोग उच्च जाति के नेताओं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गये । इसका मुख्य कारण यह भी था कि उस समय पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक–राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी। पिछड़े वर्ग की प्रमुख जातियाँ– कुर्मी, कोइरी, यादव, बनिया, दास, पासवान इत्यादि थे जिसका जीवकोपार्जन का प्राथमिक स्त्रोत मुख्यतः कृषि ही था। बिहार की पिछड़ी जातियाँ अपने दैनिक कार्यो में इतना व्यस्त थी कि चाह कर भी अपनी जाति में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं कर पायी।

उपरोक्त 38 वर्षों में बिहार की राजनीति में पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियों के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का अवलोकन करने से हमें यह जानकारी मिलती है कि किसी भी पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के नेता अपने पूर्ण कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन नहीं रह सके, वहीं उच्च जाति के अधिकांश नेता पूर्ण काल के साथ–साथ दोहरे कार्यकाल तक भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। इसमें कुछेक नेता ही अर्ध कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। बिहार में वर्ष 1977 में गैर–कांग्रेसी जनता पार्टी के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने। श्री कर्पूरी ठाकुर नाई जाति से थे जिसकी संख्या बिहार में काफी कम थी। श्री कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति के लोगों का दुख–दर्द अच्छी तरह समझते थे। उसी समय केन्द्र में भी श्री मोरारजी देसाई भारत के प्रथम (गैर–कांग्रेसी) प्रधानमंत्री बने जिससे बिहार के सत्ताधारी पक्ष के नेताओं का हौसला बुलंद हुआ। एक वर्ष पश्चात् ही वर्ष 1978 में केन्द्र सरकार ने बिहार के ही श्री बी0पी0 मंडल की अध्यक्षता में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया जिसने वर्ष 1980 में अपना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपा परंतु केन्द्र में सत्ता परिवर्त्तन हुआ तत्पश्चात केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनी जिससे रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के हाथ में चला गया और इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पुनः वर्ष 1989 में केन्द्र में जनता दल की सरकार बनी और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल रिपोर्ट को लागू कर पिछड़ी जाति के लोगों में जान डाल दिया। मंडल रिपोर्ट में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार वर्ष 1990 से पूर्व श्री कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की पिछड़ी जाति में राजनीतिक चेतना लाने के लिए काफी प्रयास किये, फिर भी पिछड़ी जाति बिहार की मुख्य राजनीति में उभरकर सामने नहीं आ सकी।

इस प्रकार देखा जाय तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्ष 1989 तक बिहार की राजनीति में उच्च जातियों का ही प्रभुत्व रहा। इस कालखंड में उच्च जातियाँ ही अपनी पकड़ सत्ता में बनाये रखी और सरकार चलाती रही।

(ख) वर्ष 1990 से वर्त्तमान समय तक का कालखंड

यह सच है कि 1970 के बाद बिहार की मंथर गति से ही हुआ। पिछड़ी जातियों में कर्पूरी ठाकुर द्वारा घोषित 26 प्रतिशत का आरक्षण, बी0पी0 सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग के अन्तर्गत 27 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़ों को मिल जाने से उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दशा में सुधार होने लगा है। साथ ही राजनीति में भी पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ती गई जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार की राजनीति में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ को पीछे छोड़ यादव, कुर्मी, कोइरी, मांझी ने सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वर्ष 1990 से अब तक निम्नलिखित मुख्यमंत्री बने–

क्रमांक	मुख्यमंत्री का नाम	कार्यकाल	जाति
1	लालू प्रसाद यादव	10.03.1990 से 28.03.1995	यादव
2	लालू प्रसाद यादव	04.04.1995 से 25.07.1997	,,
3	श्रीमति राबड़ी देवी	25.07.1997 से 11.02.1999	,,
4	श्रीमति राबड़ी देवी	08.03.1999 से 03.03.2000	,,
5	श्री नितीष कुमार	03.03.2000 से 11.03.2000	कुर्मी
6	श्रीमति राबड़ी देवी	11.03.2000 से 07.03.2005	यादव
7	श्री नितीष कुमार	24.11.2005 से 24.11.2010	कुर्मी
8	श्री नितीष कुमार	26.11.2010 से 19.05.2014	,,
9	श्री जीतनराम मांझी	20.02.2015 से 19.11.2015	मांझी (गोड)
10	श्री नितीष कुमार	22.02.2015 से 19.11.2015	कर्मी
11	श्री नितीष कुमार	20.11.2015 से 16.11.2020	,,
12	श्री नितीष कुमार	16.11.2020 से अबतक (2023)	,,

स्त्रोत–लेखक

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990 में हुए चुनाव में पिछड़े जाति के नेता श्री लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने

पिछले 33 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री का पिछड़े वर्ग के नेता ही बनते जा रहे है, इसमें यादव, कुर्मी और मांझी प्रमुख है।

निष्कर्ष– उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1952 से वर्ष 1989 तक बिहार की राजनीति उच्च जाति, पिछड़ी जाति, मुस्लिम तथा अनुसूचित जाति के हाथों में रही । वर्ष 1990 से वर्तमान सितम्बर 2025 तक अर्थात् विगत 35 वर्षों तक एक छत्र बिहार की सत्ता का बागडोर पिछड़ी जाति के नेताओं के हाथों में रहा है।

अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में बिहार की राजनीति में पिछड़ी जाति में राजनीतिक चेतना का विकास उच्च स्तर पर संभव हो पाया है और भविष्य में भी पिछड़ी जाति का ही बोल–बाला रहने की संभावना है।

Author's Declaration:

The views and contents expressed in this research article are solely those of the author(s). The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible for any errors, ethical misconduct, copyright infringement, defamation, or any legal consequences arising from the content. All legal and moral responsibilities lie solely with the author(s).

संदर्भ सूची–

1. कमर असहन, इमत्याज अहमद, बिहार एक परिचय, नेशनल पब्लिकेशन, 2016 पटना, (11वाँ संस्करण)
2. लालू प्रसाद यादव, नलिन वर्मा, गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा, रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड–2019, दिल्ली ।
3. कोठारी, रजनी, कास्ट इन इंडियन पोलिटिक्स, ओरियंट लांगमैन, दिल्ली, 1970
4. डॉ0 हरिनारायण ठाकु, भारत में पिछड़ा वर्ग आन्दोलन और परिवर्त्तन का नया समाजशास्त्र, कल्मज पब्लिकेशंस–2009, दिल्ली।
5. श्री कान्त, बिहार में चुनावः जाति, हिंसा और बूथ लूट, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली ।
6. मंडल कमीशन, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल, लेफ्टवर्ड बुक्स पब्लिकेशंस, 2018, दिल्ली।

Cite this Article-

'महेश कुमार पिन्टू' 'स्वतंत्र भारत में बिहार की पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना के विकास का अध्ययन', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:07, July 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i700010

Published Date- 06 July 2025